सिर्फ सरकारें बदलने से विकास संभव नहीं

नेताओं को बदलनी पड़ेगी मानसिकता ,सत्ताधीशों एवं पदाधिकारियों ने राजनीति को बनाया कमाई का जरिया, पन्ना जिले की राजनीति का कड़वा सच

सुरेश पाण्डेय

पन्ना, 25 जनवरी. सत्ता और संगठन में कर्मवीरों की लगी कतारे जन समस्याओं को अनदेखा कर क्या बताना चाह रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नगर व क्षेत्र के मतदाताओं ने नाराज होकर सत्ता परिवर्तन किया, परन्तु विगत 20 वर्षो में क्या पाया, यह सर्वविदित है.

बड़ी मात्रा में सत्ता के दलालों ने जनसेवा के नाम अधिकारियों की सांठगांठ से पुल, पुलिया, स्टाप डेम, सड़क निर्माण कर विकास की कड़ी को आंगे बढ़ाया परन्तु विकास की परिभाषा से अनभिज्ञ ये ठेकेदार, दलाल सिर्फअपना ही विकास करने में जुटे हुये है। आदिवासियों के लिये जितना बजट शासन प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक सरकार ने उपलब्ध कराई, उतनी रकम इसके पहले पूर्व सरकार के कार्यकाल में नहीं मिल पाई, परन्तु क्या उक्त रकम से सार्थक कोई विकास हो पाया। इस क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यो से किसी गरीब को रोजगार मिल पाया, क्या गरीब अतिगरीबों की संख्या कम हो पायी है, क्या सिंचाई का रकवा बढ़ पाया, क्या पेयजल संकट से राहत मिल पायी। जो कागजों में आकड़े दिखाये जा रहे है, उनसे निश्चित ही विकास की डगर-आगे तक, दिखाई दे रही है, किन्तु आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वालों की कतार बढ़ी है, हम यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से हटकर देखे तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी है, परन्तु नव युवकों की बेरोजगारी भी बढ़ी है, शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां कतारबद्ध होकर नौकरी पाने कार्यालयों में खड़े दिखाई दे रहे है, दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुये है, इस दौरान बुरे तरह से आदिवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए कुंआ, बावड़ी, झिरिया, तालाब स्टापडेम

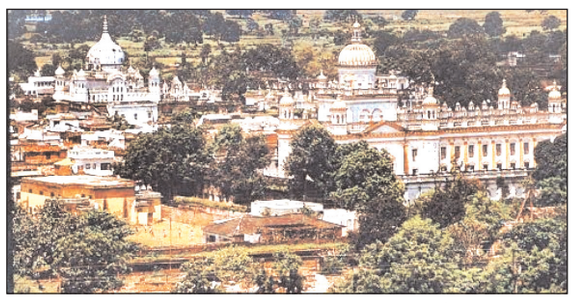

की संख्या में निर्मित किये गये जो सभी अपना अस्तित्व खोकर भ्रष्टाचार की बली चढ़ा दिये गये। सुबह से शाम तक भृष्ट उपयंत्री ठेकेदार विभागीय अधिकारी कर्मचारी हाथ से हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार की कड़ी को मजबूत करते नगर के प्रमुख स्थानों में देखे जा सकते है। इसके पूर्व भी विरोध में बैठ राजनैतिक दलों का विरोध प्रदर्शन किया जाकर नारे लगाया करते थे जो आज भी कानों में गूंज रहे है, बिजली पानी न दे सके वो सरकार निकम्मी हे, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, नारा मतदाताओं के विश्लेषण में खरा उतरा, सभी ने चिन्तन मनन किया, और निकम्मेपन में संचालित सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, अब 20 वर्षो के कार्यकाल में मतदाता पुन: उसी नारे पर चिन्तन मनन कर निर्णय करने मजबूर हो रहे है। देश की सरकार और राजनीतिक नेता इस बात में कोई रूचि नहीं दिखाते कि जीवन को आनंदमय बनाने वाले कार्यक्रम क्यों हो सकते है संघर्षमय जीवन से छुटकारा कैसे मिल सकता है। कैसे समस्या विहीन समाज की स्थापना हो सकती है देश के नेताओं के सामने तो धन बटोरने और सत्ता पर काबिज होने अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि लोग उन्हें एक अच्छा नेता कहें अच्छा प्रशासक कहें। इस बात को प्रशासनिक अधिकारी भी मानने लगे है कि समस्यायें उनके काबू से बाहर हो रही है उनका प्रशासन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। आज जो समस्यायें बढ़ रही है उनका एक मात्र कारण यह है कि लोग भौतिकता को ही सब कुछ मान बैठे है कोई भी चेतना विज्ञान को समझना नहीं चाहता।

नेताओं की मानसिकता में बदलाव से ही समस्याओं पर काबू पाना सम्भव

जब अपने ही अपने नहीं हुए तो पराये से क्या आशा करें। उक्त कथन का आशय यह है कि जब जिले में ही जन्मे और पल कर बड़े हुए और आज जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर शासन चलाने के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में भेजा लेकिन जब वे ही अपने नहीं हुए तो अधिकारियों कर्मचारियों से क्या आशा की जाये ये तो चलता जोगी बहता पानी वाली कहावत होती है। आज यहां तो कल के राजनेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका जिले के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यदि वर्तमान परिवेश में नेता को लेता कह दें एवं जनप्रतिनिधि को धनप्रतिनिधि कह दे तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। आज सारी समस्याओं की जड़ में राजनीतिक नेता प्रमख है। देश के राजनैतिक नेता भी केवल भौतिक प्रगति को ही सबसे ज्यादा महत्व देने में लगे है। आध्यात्मिक प्रगति की बात उनके गले नहीं उतरी, आदर्श व्यक्तित्व की परिभाषा उनकी दृष्टि में कुछ और ही है। वे चाहते है कि भारत भौतिक दृष्टि से सम्पन्न बने, भले ही लोग समस्याओं रोग और दुख से घिरे हो और संघर्ष का जीवन जी रहे हों।

ध्यान से होता है आंतरिक शक्तियों का विकास : बहन जी

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारी विद्यालय पन्ना की ओर से मनहर कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पन्ना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

बहनजी ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन है हमें अपना जीवन मूल्यों से सजाना होगा, अपने जीवन को नैतिक मूल्य जैसे इमानदारी, आज्ञाकारी, अनुशासन आत्मविश्वास,सत्यता आदि से मूल्यवान बनाना होगा आंतरिक शक्तियों का विकास करना होगा जीवन में दो सौंदर्य होते हैं एक आंतरिक और दूसरा बाहरी है हमें अपने जीवन को आंतरिक सौंदर्य से सजाना है, उन्होंने समझाते हुए कहा की सुबह जल्दी उठना बच्चों को मेडिटेशन ध्यान का कराया अभ्यास एवं मूल्यों को जीवन मे धारण करने की कराई प्रतिज्ञा कार्यक्रम में अमिता तिवारी, नवीन साहू एवं स्टाफउपस्थित रहा।

ट्राफिक थाना प्रभारी ने कार्यशाला में दी यातायात नियमों की जानकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. पुलिस मुख्यालय पी0टी0आर0आई0 भोपाल के आदेशानुसार प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु ''सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा'' थीम पर दिनांक 01 जनवरी से दिनांक 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है।

सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी व उनमें हो रही मृत्युदर में कमी लाया जाना है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में यातायात प्रभारी निरीक्षक नीलम लक्षकार के द्वारा पर्यटन स्तरीय कार्यशाला गल्ला मंडी पन्ना पहुंचकर उनके कार्यकर्ताओं एवं सदस्यगणों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि तेजगति गति से वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चालन, ब्रेकिंग डिस्टेन्स न रखना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाना, ओवरलोडिंग वाहन एवं खराब सड़के रोड एक्सीडेन्ट के लिए जिम्मेदार है, इनसे बचने के लिए यातायात नियमों का पालन कर निर्धारित गति में वाहन चालन, हेलमेट, सीटबेल्ट जैसे इक्युमेण्ट का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि राहवीर योजना के तहत वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल, ट्रामा सेंटर पहुंचाकर मदद करने वाले व्यक्तियों को सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय द्वारा 25 हजार रुपए नगद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिए जाने के प्रावधान है। जिससे नव युवा एवं आम आदमी पीड़ित की मदद के लिए आगे आयेंगे जिससे सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युदर में कमी परिलक्षित होगी।

मुख्यालयों में चल रहे कुछ अपंजीकृत व्यापारिक प्रतिष्ठान

पन्ना 25 जनवरी. पन्ना जिले में नगरीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान आज भी कार्यरत हैं जिनका पंजीयन नहीं हैं। जिनके पास न तो टिन नम्बर हैं और न ही जीएसटी मे रजिस्ट्रेशन है। इस प्रकार से खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों की चाटूकारिता एवं कृपा के सहारे उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान सेवा खुशामद की दम पर चल रहे हैं। जिसके चलते शासन को भारी राजस्व क्षति उठानी पड़ रही है। जब अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत वर्करो का कोई रिकार्ड ही नहीं है। जिला मुख्यालय सहित नगरीय निकायों में कई ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसमें किराना, जनरल स्टोर, सुपर मार्केट, रेडीमेट एवं कटपीस कपड़ा दुकानें हैं जहां पर कभी खरीददारों को न तो कोई रसीद दी जाती है। जिससे जीएसटी की टैक्स चोरी खुलेआम हो रही है।

कहां गया खाद्य सुरक्षा कानून : फल-फूल रहा खाने में मिलावट का धंधा

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी.जहां एक ओर सरकार लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर दिख रही है वहीं कुछ लालची दुकानदार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे है। यह सब कुछ हो रहा है खाने-पीने के सामान में मिलावट के जरिए।

पन्ना के बाजारों में खुलेआम मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं दुकानदार घटतौली के साथ मनमाने दाम पर सामान बेचते है, जिससे लोगों की जहां जेब कट रही है वहीं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में रोष है। एक तरफ तो खाद्य पदार्थो के भाव सातवें आसमान पर हैं वहीं दूसरी तरफउनमें मिलावट भी देखी जा रही है। इससे लोगों को पूरे दाम चुकाने के बाद भी शुद्ध चीज नहीं मिल पा रही है। नतीजा इन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। गंभीर बात यह है कि बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहे है इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को भी है। बावजूद इसके मिलावट खोरी के खिलाफमुहिम चलाकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पन्ना में फल सब्जियां काफी दूर से आती है, इसलिए सामान्य परिस्थिति में सेव और अनार,पपीता जैसे फल मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते है। इससे बचने के लिए व्यापारी मसाला यानी कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते है जो फलों को पकने की गति धीमी कर देते है। इसके अलावा ताजा दिखने के लिए अक्सर कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।

सभी में हो रही मिलावट- बाजार में जो खाद्य पदार्थ मिल रहे है उन सभी में मिलावट की जा रही है। यहां दूध, घी, तेल, मिर्च-मसाले सहित अन्य खान-पान की वस्तुओं में भी मिलावट की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ कोई व्यक्ति या फर्म बेच रही हो। यहां तो सभी जगह मिलावटी सामान बेचा जा रहा है।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थो में मिलावट के तौर पर जो कैमिकल्स इस्तेमाल किए जाते है वे स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी नुकसानदायक है। इनके लगातार सेवन से उल्टी, दस्त, लीवर, किडनी सहित पेट संबंधी रोग हो सकते है। मिलावटी तेल या घी कोलेस्ट्राल बढ़ाता है और इससे हृदय संबंधी रोग पनप सकते है।

चिकित्सक की सलाह

चिकित्सकों के अनुसार खुले खाद्य पदार्थ का सेवन वैसे ही नुकसानदायक है। गर्मी तथा बारिश में संक्रामक बीमारियों की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। दूषित खाद्य पदार्थो के सेवन से डायरिया, लीवर, वायरल, समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खुले खाने-पीने के सामानों पर धूल और गंदगी के साथ वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है, जिससे डायरिया, उल्टी दस्त और अन्य तमाम बीमारियां फैल जाती है।

श्रीमद् भागवत कथा का परिवार सहित भक्त ले रहे लाभ

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 25 जनवरी. नगर परिषद गुनौर अंतर्गत ग्राम सिली में राजेंद्र चौबे की स्वर्गीय माताजी हरीबाई की अर्धवार्षिकी समय के अवसर पर पुण्य आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है.

कथा प्रवक्ता पंडित श्री राम नारायण शुक्ला जी द्वारा व्यास पीठ से भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में लोक कल्यार्थ की गई लीलाओं का वर्णन भक्ति भाव से भक्तों को रसास्वाद कराया जा रहा है। आज की कथा में भगवान के

अवतारों का वर्णन श्री वेदव्यास जी द्वारा लिखे गए पुराणों का वर्णन सहित कौरव पाण्डवों के युद्ध की कथा कही। कथा में ग्राम वासियो सहित क्षेत्रीय जन पहुंचकर धर्म लाभ उठा रहे हैं।

16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पर कलेक्टर ने बीएलओ को किया सम्मानित

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार के मुख्य आतिथ्य में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का गरिमामय आयोजन रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया।

इस मौके पर मतदाताओं को प्रत्येक मतदान में निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों एवं निर्वाचन दायित्वों के बेहतर निर्वहन पर संबंधित लोकसेवकों को भी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व बताया गया तथा देश के लोकतंत्र बनने सहित चुनाव में नवाचार एवं ईव्हीएम व वीवीपैट के उपयोग की जानकारी भी दी गई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का संदेश भी सुनाया गया तथा मतदान की प्रक्रिया में सहभागिता करने की अपील की गई।

कलेक्टर श्रीमती परमार ने कार्यक्रम के दौरान एसआईआर के विभिन्न चरणों में बूथ लेवल अधिकारियों के सक्रिय योगदान व सहयोग की सराहना की। साथ ही आगामी चरण में भी समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे एवं निर्वाचन पर्यवेक्षक उमाशंकर दुबे सहित अन्य निर्वाचन टीम की कार्यकुशलता के कारण फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जिले की प्रगति अच्छी रही।

अपर कलेक्टर द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित कर निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता के अधिकार और भूमिका के बारे में बताया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सफल आयोजन किया गया।

मूलभूत सुविधाओं की वजाय सिर्फ टैक्स वसूली तक सीमित नगरीय निकाय

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. शासन और प्रशासन नागरिक सुविधाओं के नाम पर भले ही कितनी भी डींगे हांके लेकिन उनके तमाम दावों एवं योजनाओं के बावजूद शहर और कस्बों में उनकी नागरिकीय सुविधाएं एवं अधिकार महफूज नहीं है।

शहरी नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं सिकुड़कर जैसे जैसे तंग होती जा रही हैं वैसे वैसे भी ही शहर और महानगरों पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्थानीय निकाय जिनका गठन महज नागरिकों को आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है ऐसे निकाय भी अब नागरिक सुविधाओं के नाम पर सिर्फ टैक्स वसूलने वाली संस्थायें बनकर रह गई है। अब इन हालातों में स्थानीय संस्थाओं से उपेक्षित जनमानस अपनी बुनियादी एवं नागरिकीय सुविधाओं कर अपेक्षा भी करे तो किससे आखिर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिये बनी स्थानीय संस्थाएं भी सुविधाओं के नाम पर उससे छल करने पर आमादा है। गौरतलब है कि शिक्षा एवं रोजगार की तलाश मे इन दिनों लोग कस्बों और गांवों से शहरी चकाचौंध भरे जीवन के आकर्षण में गांव एवं कस्बों से शहरों की ओर पलायन की रफ्तार थमने के बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। पलायन की इसी तेज रफ्तार से शहरों और महानगरों की नागरिक एवं बुनियादी सुविधायें चरमरा गई हैं। शहरों की चकाचौंध के बीच रोजगार एंव अन्य कारणों से शहरों की ओर रूख करने वाले लोगों का जीवन झुग्गी झोपड़ियों की तंग बस्तियों में घुट जाने को मजबूर हैं। जहां उनके पास ओढ़ने के लिये खुला आकाश एवं बिछाने के लिये धरती का बिछौना तो है लेकिन पीने के लिये पानी, साफसफाई एवं स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं से कोई वास्ता नहीं।

अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डाले तो स्थानीय निकाय भी अपने नागरिकों को अक्सर वे सुविधायें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जिनको दिलाने के नाम पर निकायों का गठन किया गया है। कहने को पानी, बिजली, और सड़क वे बुनियादी जरूरत हैं जिनकी हर शहरी नागरिक को दरकार होती है।

सड़क, बिजली और पेयजल जैसी जरूरी नागरिक सुविधाओं के कागजी आंकड़े भले ही कुछ भी कहें लेकिन इनकी जमीनी हकीकत एकदम विपरीत है। शुद्ध पेयजल के तमाम दावों के बावजूद गंदा बदबूदार एवं बीमारीयुक्त पानी प्रदाय किये जाने का रोना सब दूर का रोना है। उसके भी नियमित प्रदाय किये जाने की कोई गारंटी नहीं। शुद्ध पेयजल प्रदाय की वस्तु स्थिति इससे भी बहुत आगे है। यह हालात किन्हीं की झुग्गी बस्तियों अथवा अविकसित कालोनियां के बजाय कहीं कहीं विकसित एवं पॉश एरिया में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे मे जहां लोगों को पीने का शुद्ध पानी मयस्सर नहीं वहां सड़क, बिजली सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को जिक्र करना ही बेमानी है।

सिर्फ टैक्स वसूलते हैं स्थानीय निकाय

स्थानीय निकाय नागरिक सुविधाओं के नाम पर सिर्फटैक्स वसूल करने वाली संस्थायें हैं। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होने के बावजूद नगरीय निकाय नागरिकों को सुविधाओं मुहैया कराने के बजाय अपना ध्यान कर वसूली पर ही अधिक केंद्रित रखते है। इस बात से उन्हें ज्यादा सरोकार नहीं रहता कि जिन सुविधाओं के नाम पर जनता से जो शुल्क वसूला जा रहा है वे सुविधायें भी उन्हें मिल रही हैं अथवा नहीं। कई बार तो हालत यह बन जाते हैं कि नागरिकों द्वारा कई बार शिकायत किये जाने के बावजूद उनकी सुविधायें तो लगातार कई महीनों तक बहाल नहीं हो पाती लेकिन उन्हें इन सुविधाओं के बदले निकाय को दिया जाने वाला टैक्स पूरा चुकाना पड़ता है।

मन की बात में प्रधानमंत्री ने की वनरक्षक जगदीश अहिरवार के कार्यों की सराहना

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के दक्षिण वनमंडल में पदस्थ बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार के कार्यों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उनका प्रयास अत्यंत प्रेरणादायी है। उनकी वर्षों की मेहनत से संकलित जानकारियों पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित की जा चुकी है, जो वन विभाग के साथ-साथ शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध

हो रही है। जगदीश प्रसाद अहिरवार दक्षिण पन्ना वनमण्डल की मोहन्द्रा रेंज में बीटगार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने जंगलों में पाए जाने वाले 130 औषधीय पौधों की पहचान की और प्रत्येक पौधे की तस्वीर, नाम तथा औषधीय उपयोग से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रूप से संकलित की है। यह जानकारी वर्तमान में शोधकर्ताओं, छात्रों और वनकर्मियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है।

नर्मदा का पानी पहुंचेगा कटनी और नागौद, जिले के जनप्रतिनिधि नहीं ला सके केन का पानी

तत्कालीन सांसद नागेंद्र सिंह अपने पैतृक नगर नागौद लाये थे नर्मदा का पानी, जिले के अंदर ही केन का नहीं ला सके पानी

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 जनवरी. आजादी के सात दशक बाद भी पन्ना जिला मुख्यालय मे जल स्त्रोत वहीं पुराने है जिनके द्वारा जिला मुख्यालय मे पानी की सप्लाई की जा रही है। जबकी पन्ना नगर की जन संख्या लगभग एक लाख पहुंच रही है जिससे पेयजल की समस्या लगातार बढती जा रही है।

जिला मुख्यालय मे नगर के तालाबो निरपत सागर, धरम सागर तथा लोक पाल सागर से पेय जल की सप्लाई की जाती है यह सप्लाई वही पुराने 50 साल की योजना के तहत चल रही है जब जिला मुख्यालय की जन संख्या लगभग 20 हजार रही होगी। राजाशाही के समय बनें तालाबो की पेयजल व्यवस्था आज भी जारी है तालाबों पर लोगो द्वारा लगातार भारी अतिक्रमण किया गया तथा तालाबों के भराव के स्त्रोत भी बंद हो गए है जिससे तालाबों की क्षमता के अनुसार भी पानी तालाबों मे नही आ पाता है तथा पानी का उपयोग मे लगातार वृद्धि होती गई। जिला प्रशासन तथा नगर पालिका द्वारा पेयजल के लिए प्रतिवर्ष करोडो रूपये की राशि खर्च की जाती है लेकिन स्थाई व्यवस्था न होना तथा तालाबों के गहरी करण एवं उनके भरने के स्त्रोत विकसित न होने से पर्याप्त मात्रा मे तालाबों मे पानी नही आ पाता है। इस लिए प्रतिवर्ष गर्मी के समय पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। जिले मे लगातार बाहरी लोग सांसद बने और बिना कुछ किये चलते बने उनमें से तत्कालीन सांसद नागेंद्र सिंह भी रहे हैं जो पन्ना के पडोसी नगर सतना जिले के नागौद जो कि उनका पैतृक निवास नगर है। वहां पर बाण सागर का पानी ले आये थे लेकिन अपने जिले से सांसद निर्वाचित होने के बावजूद भी अपने ही जिले के अंदर केन नदी का पानी पन्ना नहीं ला सके। इसके लिए केवल वही भर दोषी नहीं है जितने भी बाहरी सांसद प्रत्याशी आये जिले के विधायक एवं मंत्री बने किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। जिला मुख्यालय मे पेयजल के लिए केन नदी से पानी लाने की योजना पर काम नही किया गया। जबकि नर्मदा नदी का पानी कटनी तथा बाणसागर का पानी नागोद तक लाने की योजना पडोसी जिलो मे पूरी हो गई। जबकि पन्ना जिला मुख्यायल से 20 किलोमीटर दूर केन नदी का पानी पन्ना नही लाया जा सका। स्थानीय लोगो द्वारा लगातार जिम्मेवार जन प्रतिनिधियों से उम्मीद की जा रही थी कि आखिर केन नदी का शुद्ध पेयजल पन्ना जिला मुख्यालय लाने की दिशा मे कब कार्य किया जायेगा। जिला मुख्यालय मे भीषण पेयजल संकट से उबारने के लिए केन नदी से पानी लाने की योजना निश्चित रूप से कारगर साबित हो सकती है तथा हमेशा के लिए जिला मुख्यालय मे जल संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। जिले के जिम्मेवार जन प्रतिनिधियों को जनहित के इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जिससे पेयजल की यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तथा यह योजना पूर्ण कराने वाले जन प्रतिनिधियों को जनता हमेशा याद रखेगी।